प्रकाशन का 44 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक
साप्ताहिक समाचार
ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 44 अंक-10 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 4-11 मार्च 2019 मूल्य पांच रूपए

क्या प्रदेश भाजपा किसी विस्फोट की ओर बढ़ रही है आश्रय के प्रचार अभियान से उठे सन्देह

शिमला/शैल। प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिये भाजपा के प्रत्याशी कौन होंगे अभी इसका फैसला नही हो पाया है। लेकिन इस फैसले से पहले ही मुख्यमन्त्री के अपने जिले से ही पंडित सुखराम के पौत्र और ऊर्जा मन्त्री अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने मण्डी संसदीय हल्के से अपना चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। आश्रय काफी अरसे से यह दावा करते आ रहे हैं कि वही यहां से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। जब एक सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती ने यह घोषणा की थी कि मण्डी से राम स्वरूप शर्मा ही फिर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे तब इस घोषणा पर पंडित सुखराम ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी की थी। सुखराम की प्रतिक्रिया के बाद सत्ती ने भी अपना ब्यान बदल लिया था। लेकिन अभी तक टिकटों का फैसला हुआ नही है। ऐसे में आश्रय शर्मा के प्रचार अभियान के राजनीतिक हल्कों में कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। क्योंकि यह संभव नही हो सकता कि उसके अभियान को बाप और दादा का आर्शीवाद हासिल न हो। पंडित सुखराम का प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग से विषेश स्थान है। इसलिये यह एक बड़ा सवाल हो जाता है कि यदि आश्रय को टिकट नही मिलता है तो सुखराम और अनिल का अगला कदम क्या होता है। क्योंकि पिछले दिनों यह चर्चा जोरों पर हरी है कि पंडित सुखराम कांग्रेस में वापिस जा सकते हैं। अनिल शर्मा जयराम के साथ मंत्री होने के बावजूद भी मण्डी में अपने को बहुत सुखद महसूस नही कर रहे हैं। यह चर्चा भी कई बार मुखर हो चुकी है। फिर जयराम मण्डी का नाम बदल कर माण्डव करने की बात भी कर चुके हैं और इस नाम को बदलने का प्रस्ताव पर सुखराम और अनिल शर्मा की कतई सहमति नही है। नाम बदलने का यह प्रस्ताव भाजपा /जयराम से राजनीतिक रिश्ते अलग करने का एक आसान और तात्कालिक कारण बन सकता है।

इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भी सिनेतारिका कंगना रणौत का नाम अचानक राजनीतिक हल्कों में चर्चा का विषय बन गया है। इस समय हमीरपुर ससंदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर सांसद हैं। अनुराग को प्रदेश का भविष्य का नेता भी माना जा रहा है और उन्होंने अपने काम से क्रिकेट और भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी है। लेकिन अनुराग के इस बढ़ते कद से पार्टी के भीतर ही एक बड़ा वर्ग उनका अघोषित विरोधी बना हुआ है। बल्कि चर्चा तो यहां तक है कि इसी वर्ग की धूमल को

हटवाने में बड़ी भूमिका रही है। इसी के चलते तो जयराम की सरकार बनने के बाद उठे जंजैहली प्रकरण में धमूल-जयराम के रिश्ते यहां तक पंहुच गये थे कि कुछ हल्कों में जंजैहली प्रकरण में धूमल की भूमिका होने के चर्चे चल पड़े थे। धमूल को इस चर्चा के कारण यहां तक कहना पड़ गया था कि सरकार चाहे तो उनकी भूमिका की सीआईडी से जांच करवा ले। अब इसी परिदृश्य को सामने रखकर कुछ लोगों ने कंगाना रणौत का नाम उछालकर एक नयी विसात बिच्छाई है।

यही नही मण्डी संसदीय क्षेत्र से कुल्लु से पूर्व मंत्री और सांसद रहे महेश्वर सिहं को लेकर भी यह चर्चाएं चल रही हैं कि वह भाजपा का दामन छोड़कर कभी भी कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। महेश्वर सिंह कुल्लु से विधानसभा का चुनाव हारने के बाद मण्डी से इस बार लोकसभा का उम्मीदवार होने की आसा में थे। लेकिन यहां से जब मुख्यमन्त्री की पत्नी डा. साधना ठाकुर का नाम भी संभावित उम्मीदवार के रूप में अखबारों की खबरों तक पहुंच गया तब मण्डी का सारा राजनीतिक गणित ही बदल गया है। यह एक सार्वजनिक सच है कि यदि विधानसभा चुनावों से पहले महेश्वर सिंह और पंडित सुखराम परिवार ने राजनीतिक पासा बदल न की होती तो शायद भाजपा अकेले सत्ता तक न पंहुच पाती। लेकिन आज यह दोनों अपने को भाजपा में हशिये पर धकेल दिया महसूस कर रहे हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि राजनीति में अपने को फिर स्थापित करने के लिये पासा बदल की राजनीति का सहारा ले लें। यही स्थिति हमीरपुर से भाजपा पूर्व सांसद रहे सुरेश चन्देल की रही है। पार्टी ने उन्हे "Cash for Question" में चुनावी राजनीति से बाहर कर दिया। लेकिन "Cash on camera" में आरोप तय होने के बावजूद शिमला के सांसद वीरन्द्र कश्यप को लेकर पार्टी का आचरण सुरेश चन्देल से भिन्न है। एक ही जैसे आरोप पर दो अलग-अलग नेताओं के साथ अलग-अलग आचरण होने से पार्टी की अपनी ही नीयत और नीति पर सवाल उठने स्वभाविक है। ऐसे में इस संभावना से इन्कार नही किया जा सकता कि अब सुरेश चन्देल भी पार्टी को अपनी अहमियत का अहसास कराने के लिये कोई पासा बदल के खेल पर अलम कर जायें। क्योंकि यह कतई नही माना जा सकता कि आश्रय शर्मा के प्रचार अभियान के पीछे कोई बड़ी रणनीति नही है। इस परिदृश्य में यदि आने वाले लोकसभा चुनाव का एक पूर्व आकलन किया जाये तो यह स्पष्ट झलकता है कि भाजपा के अन्दर बढ़े स्तर पर एक बड़ी खेमेबाजी चल रही है क्योंकि अभी सम्पन्न हुए बजट सत्र में जिस तरह से भाजपा के कुछ अपने ही विधायकों की अपनी ही सरकार के प्रति आक्रमकता देखने को मिली है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी के अन्दर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार वित्तिय संकट में चल रही है इसका खुलासा उस वक्त सार्वजनिक रूप से सामने आ गया जब प्रधानमन्त्री की योजना के नाम पर किसानों को दिये गये दो-दो हज़ार रूपये बैकों ने किसानों को भुगतान करने से मना कर दिया। ऐसा बैकों ने क्यों कर दिया इसका कोई संतोषजनक जवाब भी सामने नहीं आया है। इस आशय की खबरें तक छप गयी लेकिन सरकार की तरफ से इनका किसी तरह का कोई खण्डन सामने नहीं आया इसी के साथ यह चर्चा भी सामने आयी है कि इस बार सेवानिवृत कर्मचारियों को पैंशन का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाया है। जहां सरकार की एक ओर इस तरह की वित्तिय स्थिति हो वहीं पर सरकार द्वारा बड़ी लगर्ज़ी गाड़ियां खरीदा जाना सरकार की नियत और नीति पर सवाल उठेगा ही।

अभी इसी के साथ सरकार द्वारा कर्मचारी भर्तीयों को लेकर अपनायी जा रही आउटसोर्स नीति पर भी गंभीर सवाल बजट सत्र में देखने को मिले हैं। यह सही है कि सरकार ने हर गंभीर सवाल को ''सूचना एकत्रित की जा रही है'' कहकर टालने का प्रयास किया है लेकिन यह माना जा रहा है कि यह सारे सवाल चुनावों के वक्त सरकार से जवाब मांगेंगे और यही सरकार के लिये सबसे बड़ा संकट होगा।

क्या सरकार लोकसेवा आयोग को सामाजिक संस्था मानती है

विधानसभा में आये प्रश्न से उठी यह चर्चा

शिमला/शैल। विधानसभा के बजट सत्र में 5 फरवरी को भाजपा विधायक रमेश धवाला का एक प्रश्न सदन में आया था। धवाला ने सरकार से यह जानकारी मांगी थी कि (क) प्रदेश लोक सेवा आयोग में वर्तमान में श्रेणीवार कौन-कौन सदस्य हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता एंव प्रशासनिक क्षमता क्या है और (ख) सरकार क्या सदस्यों के चयन के लिये समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखती है और चयन हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं '' यह प्रश्न सदन में चर्चा में नही आ पाया था। लेकिन इसके सदन में रखे लिखित जवाब में बताया गया कि इस समय अध्यक्ष समेत पांच सदस्य कार्यरत है। इनकी शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव का भी पूरा विवरण दिया गया है। लेकिन यह नही बताया गया है कि इस समय सदस्य का एक पद खाली है। क्योंकि जब जयराम सरकार ने सत्ता संभाली थी तब सदस्यों के दो नये पद सृजित किये गये थे जिनमें से एक पर तो डा. रचना गुप्ता की नियुक्ति हो गयी थी और दूसरा अभी तक खाली चला आ रहा है।

इस समय प्रदेश की शीर्ष प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा आदि से लेकर क्लर्क की भर्ती तक के लिये दो संस्थान एक प्रदेश लोक सेवा आयोग और दूसरा अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड कार्यरत हैं। इन दोनों संस्थानों ने पिछले तीन वर्षो में 15 जनवरी 2019 तक लोक सेवा आयोग ने 2198 और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 7849 उम्मीदवारों का चयन किया है। इस चयन से यह आकंलन किया जा सकता है कि प्रदेश में कितने लोगों को पिछले तीन वर्षो में नियमियत रोजगार मिल पाया होगा। इसी के साथ यह भी सवाल उठता है कि जब दोनों संस्थानों ने पिछले तीन वर्षो में केवल दस हजार लोगों का ही चयन किया है तो क्या ऐसे

शेष पृष्ठ 8 पर............

महिलाओं की देश के विकास व संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिकाः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि महिलाओं की देश के विकास तथा संस्कृति के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश तभी आगे पड़ सकता है जब महिलाओं को सम्मान मिले तथा उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित हो।

राज्यपाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। आचार्य देवव्रत ने कहा कि महिलाओं को वेदों में बड़ा सम्मान दिया गया है। वेदों में मिलता है कि जिस समाज में महिला का सम्मान होता है वह स्वर्ग है और जहां महिलाओं की अनदेखी की जाती है वहां नेक काम भी बेकार हो जाते है।

उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध संस्कृति में महिलाओं तथा पुरुष के बीच कोई भेद नहीं किया गया है और यह सब वेदिक काल तक जारी रहा। इस काल में महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे थी और समाज का प्रमुख अंग थी। उन्होंने कहा कि मध्यकाल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई परन्तु वर्तमान में महिलाओं को समाज में वही सम्मान दिया जा रहा और आज महिलाएं विकास के हर क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज महिलाएं देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपना योगदान दे रही है और विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इनकी उपस्थिति न हो।

उन्होंने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा स्वामी दयानंद सरस्वती को याद करते हुए कहा कि इन विभूतियों ने अपने समय में समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिए अनेक आंदोलन आरंभ किए।

प्रदेश में महिलाओं की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाएं अधिक मेहनती और शिक्षित है और वे खेतों से लेकर बड़े–बड़े पदों पर बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने देव भूमि में नशे के खिलाफ अभियान चलाने महिलाओं की सहयोगिता की आवश्यकता पर बल दिया तथा प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को पहल को अपनाने का आग्रह किया।

इससे पूर्व, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह ने राज्यपाल को सम्मानित किया तथा प्रदेश में महिला कल्याण के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक की पोषण अभियान में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सराहना की तथा कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश द्वारा इस दिशा में किए गए कार्यों को सराहा है।

उन्होंने कहा कि विभाग स्थानीय उत्पादों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने प्रदेश में आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना के लाभ उठाने का भी आग्रह किया।

सीआईआई उत्तरी क्षेत्र को मिले नए पदाधिकारी

शिमला/शैल। जैकसन ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर गुप्ता को सीआईआई उत्तरी क्षेत्र का वर्ष 2019–20 के लिए चेयरमैन तथा त्रिवेणी टरबाइंस के वाइस चेयरमैन व प्रबंध निदेशक निखिल साहनी को वाइस चेयरमैन चुना गया है। सीआईआई की रिजनल काउंसिल के नव नियुक्त सदस्यों की पहली बैठक के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ के उत्तरी क्षेत्र कार्यालय में हुए चुनाव में उत्तरी क्षेत्र के लिए इन पदाधिकारियों को चुना गया है।

समीर गुप्ता को अब उत्तरी क्षेत्र जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व यूटी चंडीगढ़ का प्रभार सौंपा गया है। वर्ष 2019–20 के लिए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी तैयार करने के लिए आधार बनाना, कौशल विकास और समावेशिता तथा समकालीन प्रौद्योगिकी और नवाचारों को अपनाना और औद्योगिक विकास के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करना उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होंगे।

समीर गुप्ता जैक्सन के प्रबंध निदेशक हैं जो देश की तेजी से बढ़ती डाइवर्सिफाइड पावर कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के तीन बिजनेस वटकल हैं जिनमें जनरेटिंग सेट बिजनेस, सोलर बिजनेस और ईपीसी बिजनेस शामिल है। इसके साथ ही 2012 में जैक्सन ग्रुप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी प्रवेश कर चुका है।

गुप्ता भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। वह सीआईआई उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग सोसायटी उत्तर प्रदेश चैप्टर के चेयरमैन तथा सीआईआई उत्तरी क्षेत्र की फैमिली बिजनेस नेटवर्क पर रीजनल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं।

निखिल साहनी त्रिवेणी टरबाइंस लिमिटेड के वाइस चेयरमैन व प्रबंध निदेशक तथा त्रिवेणी इंजीनियरिंग व इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा जीई त्रिवेणी लिमिटेड के निदेशक हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी तेजी से बढ़ रही है और कंपनी चीनी निर्माण के साथ ही मैकेनिकल उपकरणों का निर्माण करती है जिसके देश भर में 14 केंद्र हैं। उनका सिद्धांत जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक का है और उन्होंने बहुत से कम्यूनिटी इनिशिएटिव लिए हैं जिनमें ग्रामीण समुदाय आधारित स्वयं सहायता कार्यक्रम तथा सस्टनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव जो त्रिवेणी के ढाई लाख गन्ना उत्पादकों को फायदा देता है। उन्होंने सीआईआई त्रिवेणी वाटर इंस्टीटयूट को स्थापित करने में सहायता की और वह तीर्थ राम शाह चौरिटेबल हॉस्पिटल के एक्टिव ट्रस्टी भी हैं। इसके साथ ही वह एस्पेन इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया तथा एस्पेन ग्लोबल लीडरशिप नेटवर्क के फैलो भी रह चुके हैं। वह सीआईआई की कैपिटल गुड्स व इंजीनियरिंग पर सीआईआई की नेशनल कमेटी के को–चेयरमैन है तथा सीआईआई मैनुफैक्चुरिंग काउंसिल के वर्ष 2015–16 के लिए सदस्य भी रह चुके हैं।

7 एकड़ भूमि पर 27.95 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा स्टेट ऑफ आर्ट परिसरः मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश का युवा रोजगार ढूंढने के बजाय रोजगार प्रदाता बन सके।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर राष्ट्रीय महिला कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखने के उपरांत बोल रहे थे।

इस संस्थान की स्वीकृति केन्द्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के महानिदेशालय द्वारा प्रदान की गई है तथा वर्तमान में यह संस्थान शिमला जिले के शामलाघाट स्थित डाईट परिसर से कार्य कर रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के युवाओं के कौशल उन्नयन पर विशेष ध्यान दे रहे है ताकि आने वाले समय में देश विश्वभर के लिए कुशल कामगार उपलब्ध करवाने वाले सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि यह संस्थान न केवल महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा बल्कि महिला सशक्तिकरण में भी कारगर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान के स्थायी परिसर निर्माण के लिए शिमला के निकट झुंडला में 7 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि इस भूमि के टूकड़े पर 27.95 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट ऑफ आर्ट परिसर बनाया जाएगा। इस भवन का निर्माण एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की और से इस परिसर के शीघ्र निर्माण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस परिसर में संस्थागत खण्ड, आवासीय खण्ड, लड़कियों के लिए आधुनिक सुविधा से सुसज्जित छात्रावास, विश्राम गृह में विस्तार में एक का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण मित्र भवन होगा, जिसमें सौर पैनलिंग व वर्षा जल संग्रहण ढांचे की सुविधा होगी।

इससे बेहतर उद्योग–संस्थान समन्वय तथा स्थापित करना सुनिश्चित होगा। संस्थान में 5 विषय, जिसमें फैंशन डिजाईनिंग एवं प्रौद्योगिकी, कॉस्मैटोलॉजी, डैस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप तथा सिविल ड्राफ्टसमैन के पाठ्यक्रम होंगे तथा सभी पाठ्यक्रमों में 20 सीटों का प्रावधान किया गया है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate/percentage rate tender on Form No. 6&8 are hereby invited by the **Executive Engineer, Arki Division, HP, PWD.** Arki on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the following works from the competent (In this regard the decision of the **Executive Engineer shall be final) contractors enlisted with HP, PWD** in appropriate class whose registration stood renewed as per revised instruction and also registered dealers under the Himachal Pradesh sales Tax Act, 1968. The application for tender form will be received on **29.3.2019 upto 4.00 P.M**. The tender form will be issued on **30.3.2019. upto 4.00 P.M.** The tender form will be received on **1.4.2019. up to 10.30 A.M.** and will be opened on the same day at **11.00 A.M**. in the presence of the contractors or their authorized representative who may like to be present. The form can be had from this office against cash payment as shown below (Non refundable) during the working hours on **29.3.2019** The earnest money should be deposited in the shape of National Saving certificate, Time deposit/ Post Office saving bank account in any of the Post Office in H.P. duly pledged in the name of the Executive Engineer, Arki Division, HP, PWD. Arki and tender form will be issued only those contractors who will deposit the Earnest Money at the time of sale of tender. The conditional tenders shall not be entertained. If holiday is declared suddenly by the govt. on the above date due to some reason the tender shall be received and opened on the next working day. The intending contractors/firms will have to produce all required documents at the time of making application such as Income Tax clearance certificate for the proceeding year, registration/renewal of registration and sales tax number (Under H.P.G.S.T.) Act. Special care should be taken to write the rates both in figures and in words, failing which their tender will be rejected. No tender form shall be issued to the contractors/firms who have already two works in HP.PWD. The offer of the tender shall remain open for 120 days from the date of opening of the tender. The Executive Engineer reserves the right to accept or reject the tender without assigning any reason.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Form	Cost of form	Time period
Construction of type-II qtrs one No at Arki(SH:-Civil work	4,95,534/-	10000/-	6&8	350/-	3 Months

TERMS & CONDITIONS:-The tender documents shall be issued only to those contractors/firms who fulfill the following criteria:-

The latest renewal of enlistment/proof of valid registration and income tax clearance certificate/Permanent Account Number (PAN) must accompany the request for obtaining the tender documents.

2. The contractor should be registered under H.P. General Sale Tax Act.1968 and a proof there.of.must.accompany the request for obtaining the tender documents.
3. The applications for obtaining tender documents must be accompanied with earnest money in the shape of National Saving certificate/Time deposit account in any of the Post Office in H.P./F.D.R. from any Nationalized Bank duly pledged in favour of the Executive Engineer. Tender applications received without Earnest Money shall not be entertained and out rightly rejected and no tender form will be issued.
4. Ambiguous/telegraphic/Conditional tenders or tender by fax/E-mail shall not be entertained/considered and will summarily be rejected.
5. The Assistant Engineer, reserve the right to reject/cancel any or all the tenders without assigning any reasons.
6. The offer of the tender shall remain valid upto 120 days after the opening of tender.

Adv. No.-5256/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक– बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक–जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार–ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
*** NOTICE INVITING TENDER ***

Sealed item rate tender on form No. 6 & 8 are hereby invited by the **Executive Engineer, HP PWD Division Tanda at Nagrota Bagwan on behalf of Governor of Himachal Pradesh** for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP PWD (B & R) whose registration stood renewed as per revised rules so as to reach in his office on or before on **01.04.2019 up to 11:00 A.M.** And the same shall be opened on the same day at **11:30 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender form can be obtained from his office on cash payment (non refundable) **on 30.03.2019 up to 4:00 P.M** and the application for issue of tender form shall be received on **29.03.2019 up to 12:00 noon.** The applications for issue of tender forms accompanied with enlistment letter or renewal letter and the earnest money in the shape of National Saving Certificates/Saving Account of the Post Office /Time Deposit account/FDR in Himachal Pradesh duly pledged in favour of **Executive Engineer, HP PWD Division Tanda at Nagrota Bagwan.**

The conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for **120 days.**

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Time period
1. Restoration of rain damages on Hachichik Bag Nehar Palahchaklu road Km 0/000 to 6/100 in Distt Kangra (HP) (SH:-Providing and laying WBM G-II at RD 5/000 to 6/100).	2,47,526/-	4950/-	Two months
2. Providing way side facilities on Kangra Tanda road near flour mills in Distt kangra (HP) (SH:-construction of RCC structure and site development etc;)	2,77,271/-	5550/-	Two months
3. Restoration of rain damage on Nagrota Massal Rajhoon road Km 0/000 to 8/000 (SH:-C/O R/Wall at RD 7/165 to 7/180(L=15.00 mtr) Ht=5.48 mtr.)	4,55,064/-	9,200/-	Three months
4. Restoration of rain damages on Nagrota Masal Rajhonn road Km 0/000 to 8/000 (SH:-C/O R/Wall at RD 7/180 to 7/198 (L=15.00mtr) (HT=5.48 mtr.)	4,55,064/-	9,200/-	Three months

Terms &Conditions:-
1. The contractor/firm should be registered as or dealer GST No.
2. The intending contractor / firm have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HPPWD.
3. If any of the date mentioned above happened to be Gazetted Holidays the same shall be processed on next working day.
4. The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/application or all tenders without assigning any reason.
5. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand.
6. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-5211/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक उत्थान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता:विपिन सिंह परमार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक उत्थान तथा उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री फरेड में जिला स्तरीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला एवम् बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने के उपरांत बोल रहे थे।

उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी गांव में महिलाओं तक पहुंचाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ क्षेत्रों में घटते

लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के अंतर्गत जिला में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करने के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों को लेकर भी जागरूकता पर बल दिया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसी सभी विधवाएं जोकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हों प्रदेश सरकार की हिमकेअर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिना कोई प्रीमियम दिये, पांच लाख रुपये तक का स्वस्थ बीमा लाभ पाने की पात्र होंगी। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष परित्यक्ता महिलाओं, विधवाओं को दो बच्चों के पालन-पोषण हेतु प्रति बच्चा, प्रति वर्ष सहायता राशि को 5 हजार से बढ़ाकर छः हजार रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'शक्ति बटन ऐप' तथा महिलाओं के प्रति हिंसक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 'गुड़िया हेल्पलाइन' 1515 आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत चिकित्सा संस्थान में प्रसव कराने पर दी जाने वाली 700 रुपये की राशि के अतिरिक्त अस्पताल में जन्में सभी नवजात शिशुओं को 1500 रुपये मूल्य की ''नव आगंतुक किट'' भी दी जाएगी। उन्होंने सभी महिलाओं से हिमकेयर योजना का कार्ड बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अतिरिक्त मासिक अंशदान को मिलाकर अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक मानदेय 6300 रुपये होगा। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार ने आंगनबाड़ी सहायकों का मासिक मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये तथा मिनी आंगनबाड़ी वर्करज का मानदेय 2250 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मासिक अंशदान को मिलाकर क्रमश 3200 रुपये एवं 4600 रुपये मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 14 लाभार्थियों को 5 लाख 60 हजार रुपये के चेक तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 31 बच्चियों को 3 लाख 56 हजार की एफडी वितरित की। स्वास्थ्य मंत्री ने पीएचसी फरेड़ को आने वाले समय में सीएचसी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही फरेड़ पीएचसी में नए 4 डॉक्टरों को नियुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने समूला सहकारी सभा के भवन को 10 लाख रुपये, चार महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अपनी एच्छिक निधि से एक लाख रूपये तथा फरेड़ में एक ट्यूबवेल लगाने की घोषणा की।

इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार ने उपस्थित महिलाओं को संम्बोधित करते हुये कहा कि महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में सरकार प्रयासरत है और इन प्रयासों से अब समाज में बदलाव भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी है अनमोल योजना, एक बूटा बेटी के नाम, कम उम्र में हुई विधवाओं के लिए नर्सिंग संस्थाओं तथा आईटीआई में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में स्थानीय स्तर पर एक स्नेहधारा नाम से स्कीम शुरू की है। जिसके अन्तर्गत असहाय निर्बल और अनाथ बच्चियों को गोद लेकर उनको पढ़ाने की व्यवस्था एनजीओ के माध्यम से प्रशासन को साथ में रखकर कर रहे हैं।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना, मदर टैरेसा मातृ संबल योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, महिला स्वरोजगार योजना व सबला योजना के अंतर्गत किशोरियों को पोषाहार और बेटी है अनमोल व बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनाओं की विस्तार से जानकारी के साथ महिलाओं के संरक्षण के लिये विशेष अधिकारों में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मातृ सुरक्षा योजना और महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यान्वित अधिनियमों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जिनमें नाटकों के माध्यम से बेटियों के महत्त्व को प्रदर्शित किया। इस दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा वीवीपैट की जानकारी भी दी गई।

जय राम ठाकुर ने रखी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कार्यालय परिसर की आधारशिला

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने टुटीकण्डी स्थित आईएसबीटी पार्किंग में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भवन आगामी कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा और इस हेल्पलाईन के स्थापित हो जाने से

प्रदेश के लोग एक क्लिक पर अपनी की शिकायतों का समाधान करवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी नागरिक 1100 नम्बर डाईल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा। उन्होंने कहा कि लोग इसके माध्यम से सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हेल्पलाइन को प्रभावशाली बनाया जाएगा और वह स्वयं और मंत्री इसकी प्रगति की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाईन के माध्यम से जनमंच में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की भी निगरानी की जाएगी। यह हेल्पलाईन प्रात: 7 बजे से शाम 10 बजे तक क्रियाशील रहेगी। इससे सरकार के कार्य में भी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से आग्रह किया कि जनहित में शुरू की जा रही इस प्रणाली को सफल बनाने में सहयोग दें। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ पंजीकृत कॉल को सिस्टम द्वारा स्वयं ही सम्बन्धित विभाग को सौंपा जाएगा। इसमें चार स्तरीय शिकायत प्रणाली की योजना बनाई गई है। स्तर-1 पर तहसील, स्तर-2 पर जिला, स्तर-3 पर मण्डल तथा स्तर-4 पर राज्य है। सभी अधिकारियों को समय सीमा में शिकायत का निवारण करना होगा। यदि समय सीमा पार हो गई है या शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो समस्या अगले स्तर पर भेज दी जाएगी। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायत बंद होगी।

इस परियोजना का निष्पादन कर रही श्यौरबिन कम्पनी के प्रबंध निदेशक अभिषेक गुप्ता ने भी इस अवसर पर सम्बोधित किया।

वीडियो कांफ्रैंस से पोषण अभियान के तहत चल रही गतिविधियों की दी जानकारी

शिमला/शैल। निदेशक महिला एवं बाल विकास राजेश शर्मा ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास के साथ की गई वीडियो कांफ्रैंस में प्रदेश में पोषण अभियान के तहत एक साल से चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदेश में 8 मार्च, से 22 मार्च, 2019 तक पोषण पखवाड़े के तहत सम्बद्ध विभागों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला व खंड, पंचायत स्तर पर पोषाहार के बारे में शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा हर आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों को भी पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पोषण पखवाड़े के दौरान आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, स्कूली विद्यार्थियों, युवा व महिला मंडलो द्वारा प्रभात फेरी, रेलियां तथा बैठकों के माध्यम से संतुलित आहार को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा शिविरों के माध्यम से महिलाओं व किशोरियों में खून की कमी, आहार में पौष्टिक तत्वों के समावेश के बारे में जागरूकता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने सम्बद्ध विभागों को पोषण पखवाडे के सफल आयोजन के लिए आवश्यक विचार विमर्श किया तथा अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

50 महाविद्यालयों में होंगी भाषा प्रयोगशालाएं: सरवीन चौधरी

शिमला/शैल। राज्य के 50 महाविद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें अन्य भाषाओं के अलावा संस्कृत भाषा बोलने और सीखने का प्रावधान भी किया जायेगा।

यह उद्गार शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी ने राजकीय महाविद्यालय तकीपुर के तीसरे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह

में बतौर मुख्यातिथि अपने सम्बोधन में व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन शहरी विकास मंत्री ने कहा कि 9.90 करोड़ से बनाये जा रहे राजकीय महाविद्यालय तकीपुर के भवन का 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है और शेष कार्य को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं और इस दिशा में नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्रयासरत है और बच्चों की गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ संस्कारयुक्त शिक्षा पर बल दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बच्चे नशे रूपी कुरीति से दूर रहें और पढ़ाई के साथ साथ अन्य अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें। विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े ताकि वे अपना मुकाम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज समाज सुधार में सराहनीय योगदान दे रहीं हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में सफल वही होते हैं जो अपने सपनों को साकार करने में मेहनत करते हैं। उन्होंने महाविद्यालय प्रबंधन की सफल कार्यक्रम के लिए सराहना की। उन्होंने देश की रक्षा में लगे सैनिकों नमन करते हुए कहा कि कुछ लोग देश की सेना के द्वारा किये गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उनको घटिया बयानबाजी से दूर रहना चाहिए ताकि सैनिकों के मनोबल कम न हो। शहरी विकास मंत्री ने महाविद्यालय के लिए एक हैंडपम्प लगाने व सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 15 हजार रुपये देने की घोषणा की व शेष माँगों को शिक्षा विभाग को भेजकर पूरा करवाने को कहा। महाविद्यालय की प्रधानाचार्या सपना बंटा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया व वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा व महाविद्यालय में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों बारे जानकारी दी तथा महाविद्यालय की माँगों को शहरी विकास मंत्री के सम्मुख रखा। महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। शहरी विकास मंत्री ने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

प्रदेश में अवैध शराब के प्रयोग पर निगरानी के लिए दिशा निर्देश जारी

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त राजीव शर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें अवैध शराब के उत्पादन, तस्करी एवं अवैध प्रयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।

बैठक में उत्तर, दक्षिण एवं केन्द्रीय अंचल के अंचल आयुक्तों के अतिरिक्त उत्तर, दक्षिण एवं केन्द्रीय अंचल के प्रवर्तन अंचल भी शामिल थे।

राजीव शर्मा ने अंचल प्रभारियों को इस सम्बन्ध में जिला प्रभारियों के साथ तुरंत बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए तथा सभी शराब के ठेकों, बार, रेस्त्रा तथा होटलों इत्यादि में अवैध शराब के प्रयोग के रोकथाम के लिए औचक निरिक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तस्करी संभावित तथा पड़ोसी राज्यों से सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब तस्करी पर विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए।

उन्होंने बाहरी राज्यो से प्रदेश में आने वाले वाहनों पर लोकसभा चुनाव पूर्ण होने तक विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों के आबकारी अधिकारियों के साथ अतंरराज्य समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया ताकि शराब तस्करी पर नजर रखी जा सके।

दूसरो की गलतियों से सीखो अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जायेंगी............... "चाणक्य"

सम्पादकीय

राफेल और शीर्ष अदालत

देश में राफेल विमान खरीद को लेकर लम्बे समय से बहस चली आ रही है। इस बहस का विषय यह नही है कि यह विमान खरीदे जाने चाहिये या नही। बल्कि बहस यह है कि इस खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं। इस खरीद की प्रक्रिया पर सवाल उठाये गये हैं। इस पर उठी बहस के परिणाम स्वरूप यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पंहुच गया। शीर्ष अदालत ने इस पर सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा। सरकार ने सीलबन्द लिफाफे में बिना शपथपत्र के अदालत में अपना पक्ष रखा। शीर्ष अदालत ने सरकार के पक्ष को देखकर 14 दिसम्बर को अपना यह फैसला सुना दिया कि अदालत इसमें कोई हस्तक्षेप नही करना चाहती है। सरकार ने शीर्ष अदालत के इस फैसले को अपने लिये क्लीन चिट करार दिया। लेकिन जब यह फैसला लिखित में बाहर आया तब इसमें यह आया कि इस खरीद की प्रक्रिया और उससे जुड़े सारे दस्तावेज सीएजी और फिर पीएसी के संज्ञान में रहे हैं। पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता करता है और लोकसभा में यह दायित्व कांग्रेस नेता खड़गे के पास है। खड़गे ने अदालत में रखे गये तथ्यों पर हैरत जताई और यह एकदम राष्ट्रीय विवाद बन गया। इस पर सरकार ने तुरन्त शीर्ष अदालत में इस फैसले में संशोधन करने का आग्रह कर दिया। सरकार ने इस आग्रह का तर्क दिया कि शीर्ष ने उनके जवाब में प्रयुक्त भाषा और व्याकरण को ठीक से नही समझा है। सरकार के इस आग्रह के बाद शीर्ष अदालत में इस पूरे फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिकाएं आ गयी है। इसी बीच इस खरीद प्रक्रिया से जुड़े कुछ दस्तावेज प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक हिन्दु में छप गये।

शीर्ष अदालत के 14 दिसम्बर को आये फैसले पर पुन: विचार के लिये आयी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान जब हिन्दु में छपे दस्तावेजों का संज्ञान लेने का प्रश्न आया तब सरकार के अर्टानी जनरल ने यह कह दिया कि यह दस्तावेज रक्षा मन्त्रालय से चोरी हो गये हैं और इनका संज्ञान न लिया जाये। इसी के साथ अर्टानी जनरल ने यह भी कह दिया कि सरकार इस पर चोरी को प्रकरण दायर करने जा रही है क्योंकि यह सरकारी गोपनीय दस्तावेज अधिनियम के तहत एक संगीन अपराध है। अर्टानी जनरल के इस कथन के बाद इस बहस में एक पक्ष यह जुड़ गया कि यदि रक्षा मन्त्रालय में एक फाईल सुरक्षित नही रह सकती तो फिर देश कैसे सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ यह भी चर्चा चल पड़ी कि सरकार दस्तावेजों की चोरी का आरोप लगाकर प्रैस की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास करने जा रही है। अखबार पर इस आरोप के माध्यम से उसके सोर्स की जानकारी सार्वजनिक करने का दवाब बनायेगी। स्वभाविक है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार का कांड घटता है तो उसके प्रमाण तो दस्तावेजों के रूप में सरकार की फाईलों में ही होते हैं। यह फाईलें भी कोई आम सड़क या चौराहे पर पड़ी नही होती हैं। लेकिन इन फाईलों से जुड़े किसी अधिकारी /कर्मचारी की आत्मा उसे कचोटती है तब वह इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का रास्ता खोजता है। इस रास्ते की तलाश में सबसे पहले उसकी नजर प्रैस और पत्रकार पर जाती है। और जब वह सुनिश्चित हो जाता है कि इस माध्यम से यह जानकारी सार्वजनिक रूप से जनता के सामने आ जायेगी तथा उसकी पहचान भी गोपनीय रहेगी तब वह ऐसी जानकारी को सांझा कर पाता है। स्वभाविक है कि इस मामले में भी यही हुआ होगा। क्योंकि यह एक स्थापित सच है कि ''गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालों'' यदि एक अखबार साहस करके एक भ्रष्टाचार से जुड़े बड़े सच को बाहर ला रहा है तो क्या उसे दस्तावेज चोरी करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के नाम पर प्रताड़ित किया जाना चाहिये। शायद नही बल्कि ऐसे हर कदम का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिये।

राफेल खरीद में तीस हजार करोड़ का घपला होने का आरोप लग रहा है। क्या यह तीस हजार करोड़ इस देश के आम आदमी का पैसा नही है। क्या इस इतनी बड़ी चोरी के आरोप की गहन जांच नही होनी चाहिये। जब देश की रक्षा के लिये खरीदे जा रहे इन विमानों की खरीद में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो क्या उससे देश के आम आदमी के भरोसे को धक्का नही लग रहा है। यदि रक्षा सौदे में ही इतना बड़ा घपला हो रहा है तो फिर देश की सुरक्षा को इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। पाकिस्तान से तो हमारे सैनिक सामने से लड़ाई लड़ लेंगे लेकिन इन भीतर के भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा। आज जब एक अखबार ने भ्रष्टाचार को उजागर करने का इतना बड़ा साहस दिखाया है तो देश के आम आदमी को साथ देना चाहिये। यदि यह दस्तावेज गलत है तो उसके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला कायम किया जा सकता है। यदि यह दस्तावेज सही है तो इस सौदे की गहन जांच होनी चाहिये। क्योंकि जो दस्तावेज सामने आये हैं उनमें राफेल की तकनीकी जानकारीयों की कोई चर्चा नही है। केवल खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाये हैं। यदि आज शीर्ष अदालत इसकी जांच के आदेश नहीं देती है तो इससे आम आदमी के विश्वास को बहुत धक्का लगेगा क्योंकि अब तो अर्टानी जनरल ने भी यह कह दिया है कि दस्तावेज चोरी नही हुए है अखबार में उनकी फोटो कापी छपि है। इस परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है कि शीर्ष अदालत अपनी देख रेख में इसकी जांच करवाये।

मोदी विरोध की आड़ में देश का विरोध करना कितना उचित?

गौतम चौधरी

भारत – पाकिस्तान का आपसी गतिरोध कोई नया नहीं है। दोनों देशों का निर्माण ही आपसी विरोध के कारण हुआ है। फिर पाकिस्तान में आजतक जो भी शासक हुए उन्होंने पाकिस्तान की मानसिकता का निर्माण भारत विरोधा के आधार किया। इसलिए पाकिस्तान एक ऐसा देश बनकर खड़ा हुआ जिसकी विदेश नीति का हिस्सा ही भारत विरोध है। यही पाकिस्तान की सत्यता है। हालांकि भारतीय पंजाब के कुछ पत्रकार जब पाकिस्तान घूमकर आते हैं तो पाकिस्तानी अवाम की बहुत सराहना करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता युद्ध नहीं चाहती है लेकिन वहां की सरकार के कारण भारत – पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध विकसित नहीं हो पा रहे हैं।

मैं मानता हूं कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन जो सत्यता है उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। पाकिस्तान में जिस सोच की सरकार है वह भारत विरोधी है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस सत्य को हमें मानना ही होगा। ऐसे में पाकिस्तान की वकालत करना और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को देवदूत के रूप में स्थापित करना मुझे लगता है पूर्वाग्रह की चरमसीमा है।

अभी हाल ही में कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर फिदायीन हमला कर कम से कम 42 जवानों को मार दिया। उस हमले को लेकर कई प्रकार की बातें की जाती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कई सवाल खड़ किए हैं। वे सवाल अपनी जगह जायज हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार का विरोध करते – करते देश का विरोध करने लगे हैं। इसे किसी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। किसी सराकर का विरोध हम कर सकते हैं लेकिन देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों का विरोध कोई कैसे कर सकता है। नि:संदेह किसी को भी सरकार की तैयारी और अन्य मामलों पर सवाल खड़ा करने का अधिकार है लेकिन दुश्मन देश के प्रधानमंत्री का महिमामंडन और अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खालने का यह वक्त नहीं है। इससे देश की सुरक्षा में लगी एजेंसियों का मनोबल कमजोर हो जाता है और अंततोगत्वा हमारी सेना मनोवैज्ञानिक युद्ध में कमजोर पड़ जाती है। इसके देश कमजोर दिखता है और दुश्मनों को दुनिया में प्रचार करने की ताकत मिल जाती है। पुलवामा हमला और उसके बाद की कार्रवाई में कई विसंगतियां हो सकती है लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है उसमें सरकार की मन्शा पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ मीडिया में जो खबर आई कि सरकार चलाने वाली पार्टी इस मामले को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग कर रही है, यह भी नाजायज है। यदि ऐसा हो रहा है तो सत्तारूढ़ दल को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को विराम देना चाहिए और राष्ट्रहित को सर्वोपरी मानना चाहिए लेकिन जो लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यह कोई नहीं बात नहीं है। यदि कांग्रेस के लोग इस मामले में सवाल खड़ा करते हैं तो वे अपने गिरेबान में जरा झांकें तो। 26/11 की घटना उन्हीं के समय में हुई और उस घटना को लेकर उन्होंने भी एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद की हवा चलाने की कोशिश की थी। युद्ध को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करना गलत है लेकिन राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती रही है। इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है लेकिन जो लोग सरकार और पार्टी का विरोध करते – करते देश का विरोध करने लगे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या उनका इस प्रकार का विरोध जायज है?

देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियां किसी पार्टी की नहीं नहीं होती और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए लेकिन सरकार के विरोध की आड़ में देश के दुश्मनों के साथ जाकर खड़ा हो जाना यहां कहां की बुद्धिमानी है। इसे कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को बदला हुआ देश मान भी लिया फिर भी उसपर संशय बरकरार है। उसने जैश – ए – मुहम्मद पर अभी तक कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की है। जैश के कारण केवल भारत ही नहीं दुनिया परेशान है। यहां तक की चीन में इसके कारण परेशानी खड़ी होने लगी है। ऐसे में यदि पाकिस्तान यह कहता है कि भारत में चल रहे आतंकी गतिविधियों में उसकी कोई भूमिका नहीं है तो यह मानने योग्य बात नहीं है। पाकिस्तान बार – बार पुलवामा हमले के साक्ष्य की बात करता है। साक्ष्य उसी के पास है। जैसे ही पुलवामा हमला हुआ जैश सरगना ने उसकी जिम्मेदारी अपने उपर ली और वह पाकिस्तान के संरक्षण में है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है?

दूसरी बात, पाकिस्तान ने इन दिनों एक और शातिर चाल चली है। उसने नए सिरे से सिख समुदाय के लोगों को भड़काना प्रारंभ कर दिया है। हालांकि इसमें पाकिस्तान की भूमिका के साथ ही साथ पश्चिमी देशों की भूमिका भी संदिग्ध है लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह मोहरा पाकिस्तान ही बन रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की थोड़ी – सी भी हिमायत करना भारत के हितों के खिलाफ जाएगा। मसलन हमारे बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को सतर्क रहना चाहिए और ऐसी कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं लिखना, बोलना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्रवाद को घाटा हो और विश्वमंच पर हमारी स्थिति कमजोर पड़ जाए।

इन दिनों पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ रखा है। इंटेलिजेंश इनपुट का दावा है कि हमारे सैनिकों और सुरक्षा बलों में एक प्रकार की हीन भावनाओं को भरने की कोशिश की जा रही है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारे सैन्य संगठनों में विसंगतियां नहीं है लेकिन दुनिया के सैन्य संगठनों को उठाकर आप देख लें। हमारे यहां जितनी जनतांत्रिक व्यवस्था खड़ी की गयी है उतना दुनिया के बहुत कम देशों में है। जानकार सूत्रों पर भरोसा करें तो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रचार में सोशल मीडिया के अधिकतर हैंडलर पाकिस्तानी होते हैं। वे सुंदर – सुंदर लड़कियों का स्टेटस फोटो लगाकर हमारी सेना में वर्चुअल घुसपैठ कर जाते हैं और हमारे सैन्य संगठनों में दुष्प्रचार करते हैं। हालांकि हमारी एजेंशियां इस मामले को लेकर सक्रिय तो हुई हैं लेकिन जबतक भारतीय समाज का उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा तबतक वे अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में हमारा जीतना जरूरी है नहीं तो हम अपने राष्ट्रवाद को प्रभावी नहीं रख पाएंगे। मसलन हमारे बुद्धिजीवी और पत्रकारों को सतर्क रहना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे राष्ट्रवाद की सीमा का उलंघन न करें। इससे अंततोगत्वा दुश्मन को फायदा होगा और उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से समस्या का सामना करना पड़ेगा जो इस प्रकार के अनड़गल प्रचार में लगे हैं।

मछली उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव की ओर हिमाचल

हिमाचल प्रदेश की बारहमासी नदियाँ मछुआरों के ट्राउट उत्पादन के साथ-साथ मछुवारों को आय सृजन के अपार अवसर प्रदान करती हैं। राज्य सरकार मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है।

प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान 100 अतिरिक्त ट्राउट कृषि इकाइयों के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके अलावा, कार्प मछली के उत्पादन के लिए 10 हेक्टेयर में तालाबों का निर्माण भी किया जएगा। इस निर्णय से लगभग 550 और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

उत्पादन बढ़ाने के लिए मछुआरों की ट्राउट बीज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र के सहयोग से दो ट्राउट हैचरी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार निजी क्षेत्र की साझेदारी में कुल्लू जिले में एक स्मोक्ड ट्राउट और फिलेट टीनबंदी केंद्र भी स्थापित करेगी। उचित विपणन सहायता सुनिश्चित करने के लिए कांगड़ा, चंबा और शिमला जिले में एक-एक रिटेल आउटलेट निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाढ़ और भारी बारिश के कारण ट्राउट फार्मिंग इकाइयों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान मछुआरों की ट्राउट फार्मिंग इकाइयों के लिए एक बीमा योजना की घोषणा की है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष कुल 11413.99 लाख रुपये मूल्य की 9302.44 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन निजी और मत्स्य पालन विभागीय के फार्मों में किया गया। इस अवधि के दौरान 546.31 लाख कार्प बीज और 15.118 लाख ट्राउट बीज का उत्पादन निजी और विभागीय फार्म में किया गया। 287.48 लाख रुपये मूल्य का 141.668 लाख मछली बीज इस अवधि के दौरान राज्य के जलाशयों में इकट्ठा किया गया।

राज्य के 12,650 किसानों और मछुआरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत शामिल किया गया है। राज्य में एक्वाकल्चर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभागीय कार्प फार्मों में रीक्रिएक्शन एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) की स्थापना की जा रही है। राज्य के जलाशय से मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए, सीआसईएफ आरआई, बैरकपुर, कोलकाता द्वारा एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है।

मत्स्य विभाग ने 20 हेक्टेयर मछली तालाब, 110 ट्राउट इकाइयां, 11 ट्राउट हैचरी, 4 फीड मिलें और 3 खुदरा दुकानों के निर्माण का

प्रस्ताव रखा है। इन सभी ट्राउट इकाइयों और मछली तालाबों में मछली बीज एकत्रित किया जाएगा। विभाग राज्य के जलाशयों से 800 मछुआरों को 800 गिल नेट भी वितरित करेगा।

विभाग ने पशुधन बीमा योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है और केंद्र सरकार ने बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदेश को सूचित किया है।

हिमाचल प्रदेश ने कोच्चि (केरल) के केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित मछली बाजार सूचना प्रणाली के तहत मछली उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद की दिशा में पहल की है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां खरीदार अपनी मांग रख सकते हैं और विक्रेता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं। राज्य शीघ्र ही इस प्रणाली को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा है।

मछली उत्पादन संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जो मछली उत्पादों के लिए फसल के बाद के बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना करता है और उन्हें लाभकारी बाजार उपलब्ध कराता है।

वैश्विक राजनीति में भारत की बदलती भूमिका

आज का भारत गांधी का अहिंसा वादी भारत नहीं बल्कि यह न्यू इंडिया है। ये वो भारत है जो अपने गुनहगारों का पीछा करते हुए खुद को सीमाओं में नहीं बंधता। वो सीमाओं के पार जाकर साजिश के असली गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। हम शांति चाहते हैं और शांति के लिए हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं।

''डॉ. नीलम महेंद्र''

ये वो नया भारत है जो पुराने मिथक तोड़ रहा है, ये वो भारत है जो नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, ये वो भारत है जो आत्मरक्षा में जवाब दे रहा है, ये वो भारत है जिसके जवाब पर विश्व सवाल नहीं उठा रहा है।

पुलवामा हमले के जवाब में पाक स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद अब भारतीय सेना का कहना है की आतंकवाद के खिलाफ अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। ये नया भारत है जिसने एक कायराना हमले में अपने 44 वीर जवानों को खो देने के बाद केवल उसकी कड़ी निंदा करने के बजाए उसकी प्रतिक्रिया की और आज इस नए भारत की ताकत को विश्व महसूस कर रहा है।

आज विश्व इस न्यू इंडिया को केवल महसूस ही नहीं कर रहा बल्कि स्वीकार भी कर रहा है। ये वो न्यू इंडिया है जिसने विश्व को आतंकवाद की परिभाषा बदलने के लिए मजबूर कर दिया। जो भारत अब से कुछ समय पहले तक आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व में अलग थलग था आज पूरी दुनिया उसके साथ है। क्योंकि 2008 के मुंबई हमले के दौरान विश्व के जो देश इस साजिश में पाक का नाम लेने से बच रहे थे आज पुलवामा के लिए सीधे सीधे पाक को दोषी ठहरा रहे हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हर देश आतंकवाद को लेकर पकिस्तान के रुख की भर्त्सना कर रहा है। इतना ही नहीं जो अमेरिका और इरान अपनी अपनी विदेश नीति को लेकर अक्सर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं आज उनकी पाक को लेकर एक ही नीति है। फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाक को अपनी सीमा में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगनी चाहिए। जर्मनी और रूस के बयान भी इससे जुदा नहीं थे। और तो और जब पाकिस्तान ने भारत पाक तनाव का असर अफगान शांति प्रक्रिया पर पड़ने की बात कही तो अफगान सरकार ने पाक के झूठ को बेनकाब करके खुलकर भारत का समर्थन किया। दरअसल ये भारत की बहुत बढ़ी कूटनीतिक उपलब्धि है कि कल तक अन्तराष्ट्रीय मंच पर जिस पाक

प्रायोजित आतंकवाद को 'एक देश का आतंकवादी दूसरे देश का स्वतंत्रता सेनानी है' कहा जाता था आज 'आतंकवाद को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता' कहा जा रहा है।

और ये इस न्यू इंडिया की बहुत बड़ी जीत है कि आज एक तरफ विश्व के ये देश उसके साथ हैं तो दूसरी तरफ ओआईसी यानी आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक के 57 मुस्लिम देश भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाक के नहीं बल्कि भारत के साथ हैं। हाल ही में ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के कॉन्क्लेव में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का गेस्ट ऑफ ऑनर बनना और पाक का बॉयकॉट करना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऐसे माहौल में चीन भी भारत में आतंकवाद को कश्मीर की आजादी की लड़ाई साबित करने के पकिस्तान के षडयंत्र में पाक का साथ छोड़ने के लिए विवश हो रहा है। यह न्यू इंडिया की ही ताकत है कि सुयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुलवामा हमले के निंदा प्रस्ताव पर चीन को भी अपनी सहमति देनी पड़ी। क्योंकि हाल के समय में तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में इस न्यू इंडिया ने विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान और जगह दोनों बनाई है। जो भारत आज से कुछ सालों पहले तक दुनिया की नजर में सांप सपेरों का देश था आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जो भारत 1965, 1971 और 1999 में कूटनीतिक रूप से कमजोर था आज वो इस मामले में अपना लोहा मनवा चुका है। जिस राजनैतिक तीव्रता से सम्पूर्ण विश्व ने सिर्फ पुलवामा हमले की निंदा ही नहीं की बल्कि पकिस्तान को दोषी ठहराया और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को अपना समर्थन दिया वो वैश्विक राजनीति में भारत की बदली हुई भूमिका बताने के लिए काफी है ये बताने के लिए काफी है कि आज का भारत गांधी का अहिंसावादी भारत नहीं बल्कि यह न्यू इंडिया है। ये वो भारत है जो अपने गुनहगारों का पीछा करते हुए खुद को सीमाओं में नहीं बांधता। वो सीमाओं के पार जाकर साजिश के असली गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। लेकिन खास बात यह है कि एक देश की सीमा रेखा को पार कर के अपना बदल लेकर भी ये न्यू इंडिया यह स्पष्ट संदेश देने में कामयाब होता है कि यह 'हमला' नहीं है। ये वो न्यू इंडिया है जो दुनिया को यह समझाने में कामयाब हुआ है कि हम शांति चाहते हैं और शांति के लिए हम युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं।

शायद इसीलिए वो भारत जो 1971 में जेनेवा समझौते के बावजूद 90000 पाक युद्ध बंदियों और जीते हुए पाक के हिस्से के बदले अपने 54 सैनिक वापस नहीं ले पाता आज पाक को 36 घंटे के भीतर अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते भारी घरेलू विरोध के बावजूद भारतीय पायलट बिना शर्त सकुशल लौटाने के लिए बाध्य कर देता है। ये नया भारत अपनी कूटनीति से पाक और उसके हर झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब कर देता है। उस अमेरिका के साथ उसके रिश्ते की नींव ही हिला देता है जिसकी आर्थिक सहायता से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। ये वो न्यू इंडिया है जो बिना लड़े ही युद्ध जीत जाता है। और वो न्यू इंडिया जिसका पायलट मिग 21 से 16 को गिराने का हौसला और जज्बा रखता है और एक बार फिर विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है।

पीटीए/पैरा अध्यापकों को मिलेगी न्यूनतम पे-बैंड के बराबर धनराशि

शिमला/शैल। प्रदेश मंत्रिमंडल की आयोजित बैठक में उन पीटीए/पैरा अध्यापकों को न्यूनतम पे-बैंड के बराबर धनराशि, ग्रेड-पे और निर्धारित 144 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2018 को अनुबंध आधार पर अपनी सेवाकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। बढ़ी हुई दर से धनराशि 1 अप्रैल, 2019 से देय होगी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। पीटीए अध्यापकों और पीटीए नियमों, 2006 में अनुदान के तहत नियुक्त लैफ्ट आउट अध्यापकों को भी पे-बैंड व ग्रेड-पे के बराबर धनराशि और 144 प्रतिशत निर्धारित महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2018 को तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है (वर्तमान में अनुबंध आधार पर कार्यरत और पीटीए-जीआईए दोनों को)। बढ़ी हुई दरों से यह राशि 1 अप्रैल, 2019 से देय होगी।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज में हि.प्र लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की। इस मंडल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरा जाएगा।

कुल्लू सर्कल के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के कुल्लू और बंजार मंडलों में आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। नए उपमण्डल मनाली और कटराई अब मनाली मण्डल, कुल्लू, भूंतर व शॉट उपमण्डल कुल्लू मण्डल जबकि बंजार, लारजी व बजौरा, बंजार लोक निर्माण विभाग मण्डल के अधीन होंगे।

कांगड़ा जिले के थुरल सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल के अंतर्गत सुलह में नया उप-मंडल और ठाकुर द्वारा में अनुभाग खोलने का निर्णय लिया गया है। इनके लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने चम्बा जिले के तीसा के अंतर्गत भंजराडू में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया मंडल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर कृषि विस्तार अधिकारियों के 75 पदों को भरने को सहमति प्रदान की गई। इन पदों को हि.प्र कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2019 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6250 रुपये से बढ़ाकर 6300 रुपये, आंगनवाड़ी सहायकों का 3150 रुपये से 3200 रुपये और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकताओं का मानदेय 4550 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिले के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेर चौक में स्टाफ नर्सों के 62 पद और डा. राधाकृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर में स्टाफ नर्सों के 33 पद भरने का निर्णय लिया गया। ये सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।

पुलिस नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस जिला बद्दी में विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें पुलिस थाना बद्दी के लिए कांस्टेबल के 6 पद, बरोटीवाला पुलिस थाना के लिए कांस्टेबल के 5 पद, नालागढ़ व रामशहर पुलिस थानों के लिए कांस्टेबल के सात-सात पद, महिला पुलिस थाना बद्दी के लिए सब-इंस्पेक्टर का एक पद और कांस्टेबल के 6 पद, पुलिस थाना जगाह के लिए हैड कांस्टेबल का एक पद, पुलिस थाना धबोटा के लिए एएसआई का एक पद, हैड कांस्टेबल का एक पद व कांस्टेबल के पांच पद, टोल बैरियर धेरोवाल के लिए एएसआई का एक पद, टोल बैरियर बद्दी के लिए हैड कांस्टेबल के तीन पद और कांस्टेबल के 9 पद, चैक पोस्ट बघेरी के लिए एएसआई का एक पद, हैड कांस्टेबल के दो पद और कांस्टेबल के 9 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त 30 मोटर साइकिल खरीदने का भी फैसला लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के समकक्ष उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3500 रुपये का अनुदान करने के लिए दिशा-निर्देशों पर भी अपनी मुहर लगाई है।

अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए पहली से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल वर्दियां खरीदने व वितरित करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ई-टैंडर के माध्यम से करेगा।

बैठक में मण्डी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के अन्तर्गत बरछवार में एक प्रशिक्षण अकादमी/केन्द्र स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई ताकि प्रदेश के इच्छुक युवाओं को सेना, नौसेना व वायु सेना तथा अन्य अर्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

राज्य में पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यो के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुश्रवण के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग में तकनीकी शाखा के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

हाल ही में सृजित नागरिक न्यायालयों कुल्लू, बंजार, तीसा और शिलाई के लिए सहायक जिला न्यायवादी का एक-एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, इन नागरिक न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन-तीन पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के झण्डुता में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया मण्डल खोलने का निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित किए जाएंगे।

बैठक में सिरमौर जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों घरगों-प्लुशो को माध्यमिक विद्यालयों जबकि माध्यमिक पाठशाला दून-देरिया को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त कुल्लू जिला के सोयल, सिरमौर जिला के कोटला मांगण, कोटला बड़ोग व छोग टाली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 43 पद भरे जाएंगे।

मण्डी जिला के जोगेन्द्रनगर क्षेत्र के मकरीड़ी में उप-तहसील खोलने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने जोगेन्द्रनगर मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।

बैठक में मण्डी जिला के थुनाग स्थित क्षेत्रीय बागवानी एवं वानिकी विकास और विस्तार केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।

मण्डी जिला के नागरिक चिकित्सालय धर्मपुर और संधोल में बिस्तरों की क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 107 पद सृजित करने को सहमति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला में राजकीय माध्यमिक पाठशाला धेवा को स्तरोन्नत कर इसका नाम शहीद तिलक राज राजकीय माध्यमिक पाठशाला, धेवा रखने का निर्णय लिया गया।

सिराज में बनेगी प्रदेश की सबसे बड़ी जलापूर्ति योजना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 215 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले सिराज और गोहर खण्डों के लिए लंबाथाच में प्रदेश की सबसे बड़ी जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के अंतर्गत सिराज विधानसभा क्षेत्र की 58 में से 33 पंचायतों के हजारों लोगों को पेयजल सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर थुनाग में सिराज विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महा सम्मेलन को

सम्बोधित करते हुए कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से 1100 किलोमीटर लम्बी पाइप लाईन बिछाई जाएगी और अतिरिक्त घरों को पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना के कार्य के पूर्ण होने पर 163 गांवों तथा 1135 बस्तियों के हजारों लोगों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए छड़ी, बाखली, छतरी तथा थानेसर खड्डों से जल उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य के समान विकास के लिए हर क्षेत्र को अधिमान दिया गया है। पिछले एक वर्ष में प्रदेश भर में करोड़ों की लागत से बनने वाली विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण एवं आधाशिलाएं रखी गई हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की तीव्र प्रगति के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए हैं। सरकार ने पीटीए शिक्षकों के मानदेय को नियमित अध्यापकों के वेतन के बराबर किया। इससे उन्हें अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तरह राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी शीघ्र राहत प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उत्तरदायी एवं पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवा रही है। केन्द्र सरकार के साथ प्रभावी समन्वय के कारण राज्य में विकास कार्यों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के चलते भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हुए आतंकी हमले के बाद सेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में आंतकी शिवरों पर की गई एयर स्ट्राइक के सम्बन्ध में विपक्षी नेताओं द्वारा सबूत मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस अवसर पर सिराज विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 5,55,555 रुपये का चैक भेंट किया। इस अवसर पर सिराज विधानसभा क्षेत्र के हजारों कांग्रेस नेता लंबाथाच तथा थुनाग में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए तथा मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल होने वाले इन नेताओं को विश्वास दिलाया कि उन्हें पार्टी में उचित सम्मान मिलेगा।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने हि.प्र. बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत 1.33 लाख रुपये की लागत से जंजैहली विकास खण्ड के सुनाह बताहर में बनने वाली बहाव सिंचाई योजना की आधारशिला रखी। उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निहारी सुनाह में 3.76 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले अतिरिक्त भवन की भी आधारशिला रखी। उन्होंने ग्राम पंचायत कंडा के बीजाही में 7.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले ग्रामीण आजीविका केन्द्र सिराज की आधारशिला भी रखी तथा 1.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बखाली खड्ड पर बने छड़ी पुल का लोकार्पण किया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व पर प्रगति व समृद्धि की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रिमण्डल के सहयोगियों को प्रदेश के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के सम्बन्धित मामलों को उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि विकास में और तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 4751 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना स्वीकृति की है ताकि अधिक से अधिक खेतों को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाकर वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जा सके।

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत् एक वर्ष के दौरान कर्मचारियों को करोड़ो रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं।

प्रदेश में श्रमिकों को 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' शुरु

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को लाभान्वित करेगी जिनके पास आधार कार्ड तथा जनधन/अन्य बैंक खाते हैं और जिनकी आय 15 हजार रुपये से कम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के श्रमिक लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना स्वैच्छिक तथा अंशदान पर आधारित योजना है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के उपरांत लाभार्थी को कम से कम 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत श्रमिक द्वारा अंशदान की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक हो सकती है, 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे जरूरमंद लोगों के लिए पेंशन योजना आरंभ करने से प्रधानमंत्री की सभी जरूरमंद देशवासियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रमिकों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने में मील-पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिक लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत करना सुनिश्चित करें, जिससे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सकें।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर या इससे कम भूमि वाले सभी कृषकों को 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष की आय सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में इस योजना के अंतर्गत कृषकों के खातों में 30 करोड़ की राशि जमा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सभी योजनाएं सरकार की आमजन के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ऊर्जा मंत्री एवं स्थानीय विधायक अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पेंशन से वंचित थे तथा इस योजना के शुभारंभ से श्रमिकों को मासिक आय सुनिश्चित होगी।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के रिक्शा चालक, मिस्त्री, बीड़ी मजदूर, ईट भट्टा/चमड़ा उद्योग/ हस्तशिल्प और हथकरघा में कार्य करने वाले श्रमिक लाभान्वित होंगे।

लोकसभा सांसद राम स्वरूप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ अहमदाबाद से किया, जिससे देशभर के श्रमिकों के आर्थिक उत्थान में सहायता मिलेगी। श्रम आयुक्त एस.एस. गुलेरिया ने मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्यों का स्वागत किया तथा इस योजना की विशेषताओं से भी अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि इस योजना के लाभ पाने के लिए असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को 55 रुपये से 200 रुपये (आयु के अनुसार) तक की मासिक अंशदान अदा करना होगा जिसका लाभ उन्हें पंजीकरण के उपरांत पेंशन कार्ड के माध्यम से मिलेगा।

''ईमानदार प्रयास का - नया दौर विकास का''

सभी वर्गों के कल्याण

को समर्पित बजट

श्री जय राम ठाकुर
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में वर्ष 2019-20 का ₹44387 करोड़ का बजट पारित

मानदेय एवं भत्तों में बढ़ोतरी

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़कर हुई 850 रूपये। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 1,500 रूपये पेंशन।
- दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी 225 से हुई 250 रूपये।
- पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर किया 4,500 रूपये।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्रमश: 6,300, 3,200 व 4,600 रूपये मिलेंगे।
- अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी। अब ग्रेड पे का मिलेगा 125 प्रतिशत।
- वाटर गार्ड का मानदेय हुआ 3,000 रूपये।
- पम्प ऑपरेटर्ज व पैरा फिटर्ज का मानदेय हुआ 4,000 रूपये
- प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनधारकों को 1 जुलाई, 2018 से 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता।
- ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय बढ़कर हुआ 4,500 रूपये, उप-प्रधान का 3,000 रूपये तथा सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता बढ़ाकर 250 रूपये।
- पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रूपये से बढ़ाकर 7,000 रूपये किया। उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रूपये।
- पंचायत समिति सदस्यों का मानदेय 4,000 रूपये से बढ़ाकर 4,500 रूपये।
- जिला परिषद् अध्यक्ष का मानदेय 11,000 रूपये से बढ़ाकर 12,000 रूपये।
- उपाध्यक्ष का 7,500 रूपये से बढ़ाकर 8,000 रूपये।
- जिला परिषद् के सदस्यों का मानदेय 4,500 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रूपये।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या प्रदेश को मिले 70 राष्ट्रीय राजमार्गो का सरकार का दावा जुमला ही था

विधानसभा प्रश्न से उठी चर्चा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार की ओर से 70 राष्ट्रीय राजमार्ग दिये गये हैं और इन पर करीब 60 हजार करोड़ का खर्च किया जायेगा। प्रदेश सरकार यह दावा करती आ रही है क्योंकि इसकी पहली सूचना केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा के उस पत्र के माध्यम से दी गयी जो उन्हें केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी से मिला था। हिमाचल के लिये यह एक बड़ी उपलब्धि थी और इसे केन्द्र सरकार के प्रदेश के प्रति विशेष लगाव के रूप में लिया गया था। माना जा रहा था कि केन्द्र के इस सहयोग से प्रदेश की सड़कों का कायाकल्प हो जायेगा। लेकिन इस समय प्रदेश की सड़कों की हालत क्या है इसका अनुमान 'शिमला – बिलासपुर' सड़क से ही लगाया जा सकता है। इस सड़क की हालत देखकर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के होने पर ही सन्देह होने लगता है। लोक निर्माण विभाग मुख्यमन्त्री के अपने पास है और वह 63 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी कर चुके हैं लेकिन इनमें से 42 का दौरा हैलीकाप्टर से ही हुआ है क्योंकि उन्हें शयद इसीलिये मुख्यमन्त्री को जमीनी हकीकत की सही जानकारी नही है।

अभी विधानसभा के बजट सत्र में राष्ट्रीय राजमार्गो को लेकर प्रश्न आये थे। एक प्रश्न 7 फरवरी को था। इसमें पूछा गया था कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रश्न केन्द्र सरकार से उठाया गया है। इसके जवाब में बताया गया कि जी, हां। प्रदेश सरकार द्वारा 69 सैद्धान्तिक राष्ट्रीय राजमार्गो और 1 सड़क को सैद्धान्तिक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु मामला केन्द्र सरकार से उठाया गया है।

54 सड़कों की भेजी गई ड्राफ्ट सरेखण रिपोर्ट (Draft Alignment Report) की स्वीकृति और इनको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। 2 अन्य सड़कें जो राष्ट्रीय राजमार्गो के मापदण्ड के अनुरूप बनी है, भी केन्द्र सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु विचाराधीन है।

58 राष्ट्रीय राजमार्गो की Detailed Project Report (DPR) के लिए केन्द्र ने 173.75 करोड रू. की धनराशि स्वीकृत (sanction) की है। दूसरा प्रश्न 13फरवरी को आया था। इसमें पूछा गया था कि प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित है और इनमें से कितने पूरे होकर चालू हो गये हैं। इसके जवाब में कहा गया है कि प्रदेश में कुल 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसमें यह भी नही कहा गया है कि 70 राष्ट्रीय राजमार्ग सैद्धान्तिक रूप से घोषित हो चुके हैं। इस तरह एक ही मुद्दे पर दो अलग – अलग प्रश्नों पर दो अलग – अलग उत्तर आने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 70 राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा को हकीकत होने के लिये अभी लम्बा इन्तज़ार करना होगा। इसी के साथ यह भी तय है कि इन लोकसभा चुनावों में केन्द्र और राज्य सरकार के राष्ट्रीय राजमार्गो का दावा एक बड़ा मुद्दा बनकर उछलेगा। क्योंकि अब इसका प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लेते हुए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर सही स्थिति की जानकारी मांगी है।

यह है 19 राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

Reply of Starred Question No. 1512 asked by Sh. Jeet Ram Katwal (Jhanduta):

(a) There are 19 National Highways declared in the State of Himachal Pradesh with a total length of 2581 Kms.

The details of declared National Highways is in Annexure- 'A'

(b)&(C) Out of 19 numbers National Highway, 18 numbers are complete/functional in the State. 7.00 kms (seven) length of National Highway-503A (Una-Basoli-BarsarSalooni and terminating at its Junction with NH-103 near Bhota) from Km 35/00 to Km 42/00 is yet to be constructed between Bhihroo (Una District) and Lathiani (Una District) as its alignment passes along Govind Sagar reservoir. The detail of expenditure and the latest position of construction of National Highways are shown in Annexure -'B'.

NH wise detail of expenditure incurred on ongoing sanctioned projects on NH with State PWD alongwith latest status:

1. NH-22 (New NH-05) - Haryana Border-Solan, Shimla, Theog, Narkanda, Rampur, Chini and proceeding to the Border between India and Tibet near Shipkila Total Projects = 11 Total Expenditure= 97.35 crore

2. NH-72 (New NH-07) - Haryana Border-Paunta-Sahib- Uttarakhand Border Total Projects = 5 Total Expenditure= 45.09 crore

3. NH- 88 (New NH-103) - Junction with NH-3 near Hamirpur and connecting Bhota, Ghumarwain and terminating near Ghaghas on NH 154 Total Projects = 3 Total Expenditure= 270.58 crore

4. NH-21A (New NH-105) - Junction with NH-5 near Pinjore in Haryana connecting Baddi, Nalagarh and terminating at its junction with NH-205 near Swarghat Total Projects = 3 Total Expenditure= 72.36 crore

5. NH-20 & 21 (New NH-154) - The Highway starting from its Junction with NH-154 near Pathankot in Punjab connecting Nurpur-Palampur-Jogindernagar - Mandi-Sundernagar- Ghagus-Bilaspur and terminating it Junction with NH-205 near Nauni in H.P. Total Projects = 5 Total Expenditure= 46.43 crore

6. NH-21 & 88 (New NH-205) - Punjab Border-Swarghat, Nauni, Darlaghat-junction with NH-5 near Shimla Total Projects = 1 Total Expenditure= 9.29 crore

7. NH-20A & 88 (New NH-303) - Highway starting from Nagrota at Junction on NH-154 connecting Ranital-Jawalamukhi and terminating at Nadaun on NH-3 Total Projects = 1 Total Expenditure= 6.96 crore

8. NH-72B (New NH-707) - The Highway starting from its Junction with NH-7 near Poanta Sahib connecting Rajban-Shillai-Minus in H.P. and passing through Minus-Tiuni in Uttrakhand and terminating at Hatkoti in H.P. Total Projects = 2 Total Expenditure= 17.67 crore

9. NH-73A (New NH-907) - Junction with NH-7 near Paonta Sahib-Haryana Border Total Projects = 1 Total Expenditure= nil

10. New NH-305 - The Highway starting from Sainj on NH-5 connecting Luhri -Ani-Jalori- Banjar and terminating at Aut on NH-3 in the State of H.P Total Projects = 2 Total Expenditure= 27.32 crore

11. NH-70 & 21 (New NH-03) - Naduan- Hamirpur-Toni Devi- Awa Devi- Mandi-Kullu- Manali- Gramphoo-Kyelong Total Projects = 9 Total Expenditure= 37.08 crore

12. New NH-154A-Punjab Border- Banikhet-Chamba–Bharmour Total Projects = 2 Total Expenditure= 5.92 crore

13. NH–20A & 88 (New NH-503) - Punjab Border-Dehlan-Una-Amb-Junction with NH-3 at Mubarakpur connecting Dehra Gopipur, Ranital, Kangra, Mataur, Dharamshala–Macleodganj During this financial year no work is underway

-. 14. New NH-503Ext. - The Highway starting from its Junction with NH-3 near Mubarkpur connection Amb-Una-Dehlan in the State of Himachal Pradesh, Anandpur Sahib-Kiratpur and terminating at its junction with New NH No. 205 in the State of Punjab. During this financial year no work is underway

. 15. NH-503APunjab, Una, Basoli, Barsar, Salooni and terminating at its junction with NH-103 near Bhota Total Projects = 1 Total Expenditure= 22.59 crore

16. New NH-907A- Starting from its junction with NH No-7 near NahanBanethi-Sarahan& terminating at its junction with NH No.-5 near Kumarhatti During this financial year no work is underway

17. New NH-505A- Junction with NH-5 near Powari - ReckongPeo–Kalpa Total Projects = 1 Total Expenditure= 3.32 crore

18. New NH-705 - The Highway starting from its junction with New NH No. 5 at Theog connecting Kotkhai, Jubbal and terminating at its junction with NH No. 707 at Hatkoti During this financial year no work is underway

. 19. Khab-Sumbdo-Kaza-Gramphoo (BRO) Khab to Sumbdo 48 Kms. . i).Improvement to NHDL in progress. Sumdo-Kaza–Gramphoo ii) DPR is under preparation

क्या सरकार लोकसेवा

.........पृष्ठ 1 का शेष

में इन दोनो संस्थानों को चलाये रखने का औचित्य क्या है। फिर इनमें सदस्यों के नये पद सृजित करना उचित है।

लोकसेवा आयोग प्रदेश की शीर्ष राजपत्रित सेवाओं के लिये उम्मीदवारों का चयन करता है। इस चयन के लिये आयोग के सदस्य भी अपने में उच्च शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता एवम् अनुभव वाले लोग होने चाहिये। इन सदस्यों के चयन के लिये एक स्थापित और तय प्रक्रिया होनी चाहिये। इस संबंध में पंजाब लोक सेवा आयोग में फैसला देते हुए शीर्ष अदालत ने राज्यों को निर्देश दिये हैं कि वह इस चयन के लिये सुनिश्चित चयन प्रक्रिया और मानदण्डों की स्थापना करें। सर्वोच्च न्यायालय में यह भी उल्लेख आया है कि इन सदस्यों की योग्यता का मानदण्ड ऐसा रहना चाहिये जो प्रशासन में दस वर्ष तक वित्तायुक्त का अनुभव होना चाहिये और वित्तायुक्त होने की पात्रता रखता हो। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों की अनुपालना हो पा रही है जबकि यह फैसला 2014 में आ चुका था। लेकिन अब जो विधानसभा में आये प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा है उसके अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। इनकी नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद – 316 के अनुसार की जाती है, जिसमे उद्धृत प्रावधान अग्रलिखित हैं: –

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा और, यदि राज्य आयोग के लिए, के राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी – अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना (Computing) करने मे संविधान के प्रारम्भ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद – 316 (3) के अनुसार कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर, उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 319 के परिच्छेद (घ) के अन्तर्गत राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र है।

सरकार के इस जवाब से यह सवाल उठता है कि क्या सरकार लोक सेवा आयोग को कोई राजनीतिक या सामाजिक संस्था बनना चाहती है जिसमें समाज के सारे वर्गो का प्रतिनिधित्व हो। सरकार के इस जवाब से आयोग की बुनियादी अवधारणा पर ही गंभीर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधित्व से आयोग के सदस्यों की अपनी निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। हिमाचल लोक सेवा आयोग को लेकर भी एक प्रकरण प्रदेश उच्च न्यायालय मे गया हुआ है लेकिन उच्च न्यायालय पिछले दो वर्षो में इस प्रकरण की सुनवाई के लिये समय नही निकाल पाया है। इससे यह संदेह उभरना स्वभाविक ही है कि कहीं उच्च न्यायालय की नजर में भी सरकार की तरह यह एक सामाजिक संस्था ही है।